रवींद्र कुमार शॉ (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि

बनाम

मानिक लाल शॉ

22 अक्टूबर, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और लोकेश्वर सिंह पांटा, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

आदेश . 39, नियम 1, 2 और 4- वादी द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन - यथास्थिति का अंतरिम आदेश दिया गया-प्रतिवादी द्वारा अंतरिम आदेश को हटाने के लिए आवेदन- उच्च न्यायालय ने आवेदन को खारिज कर दिया i आदेश 39 नियम 1 और 2 आवश्यक पक्षों को पक्षकार नहीं बनाने पर लिए अपील - इस बीच विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकार बनाने के आवेदन को अनुमति दी गई - निर्धारित: चूंकि उच्च न्यायालय मामले के गुण-दोष पर नहीं गया , इसलिए बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए, विचारण न्यायालय पक्षों के पक्षकार बनाने के प्रभाव पर विचार करते हुए मामले पर नए सिरे से विचार करेगा।

अपीलार्थियों के हित में पूर्ववर्ती द्वारा दायर स्वामित्व और निषेधाज्ञा की घोषणा के मुकदमे में, विचारण न्यायालय ने यथास्थिति का अंतरिम

आदेश दिया। प्रतिवादी-प्रत्यर्थी द्वारा इसके खिलाफ दायर अपील में, उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि वे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 39, नियम 1 और 2 के तहत दायर निषेधाज्ञा के लिए आवेदन में गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना बाकी था। इसके बाद, आदेश 39 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता, के तहत प्रतिवादी द्वारा संत्रिम आदेश को हटाने के लिए आवेदन किया गया , उच्च न्यायालय ने वादी द्वारा दायर अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि चूंकि वादी ने प्रतिवादी के तीन बेटों को शामिल नहीं किया था, जो प्रतिवादी के साथ संपत्ति के सह-मालिक बन गए थे, इसलिए मुकदमे में आवश्यक पक्षों के अभाव में निषेधाज्ञा का कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जा सकता था ।

तत्काल अपील में, अपीलकर्ताओं द्वारा यह बताया गया कि उच्च न्यायालय ने मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर नहीं किया और आवक्श्यक पक्षकार नहीं बनाने के तकनीकी आधार पर विवादित आदेश पारित किया। उसके बाद, प्रतिवादी के तीन बेटों को मुकदमे में शामिल किया गया।

अपीलों का निस्तारण करना और मामले को विचरण न्यायालय में भेजना, न्यायालय ने निर्धारित किया : प्रतिवादी के तीन बेटों को पक्षकार बनाने को देखते हुए आवेदन की स्थिरता के बारे में मूल आपत्ति अब बनी नहीं है और इसलिए, मामले की नए सिरे से सुनवाई की आवश्यकता है।

उच्च न्यायालय ने नोट किया कि वह मामले के गुण-दोष में नहीं गया था; और केवल प्रतिवादी के तीन बेटों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के तकनीकी आधार पर, अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया था। बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए, मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए विचारण न्यायालय को भेजा जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवादी के तीन बेटों के पक्षकार बनाने के प्रभाव पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा।[पैरा 5] (604-सी, डी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

2007 की सिविल अपील सं. 4926/2007

(2005 के एफ. एम. ए. सं. 1471 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय के निर्णय और अंतिम आदेश से।)

के साथ

2007 का सी. ए. सं. 4927।

अपीलार्थी के लिए तापस रे, बिजन कुमार घोष और एस. के. पोद्दार।

उत्तरदाताओं के लिए जयदीप गुप्ता, सत्यजीत सालिया, वी. डी. खन्ना और राजकुमार लाहोली।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति दी गई।

2. इन अपीलों में चुनौती कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को दी गई है जो प्रतिवादी-मानिक लाल शॉ द्वारा दायर अपील को स्वीकार करता है।अपील प्रत्यर्थी द्वारा दायर की गई थी जो स्वामित्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे में प्रतिवादी था। 4 दिसंबर 2004 आदेश के खिलाफ भी यही निर्देश दिया गया था जो कि कलकत्ता में 10 वीं बेंच, सिटी सिविल कोर्ट द्वारा 2000 के टाइटल सूट सं .815 में विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया था , जिससे प्रतिवादी द्वारा दायर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सीपीसी') के आदेश 39 नियम 4 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया गया और वादी द्वारा दायर आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत आवेदन को अनुमति दी गई।

3. मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, आदेश 39 नियम 1 और 2 सी. पी. सी. के संदर्भ में आवेदन दायर किया गया था जिसमें निषेधाज्ञा के आदेश और प्रतिवादी को मुकदमे की संपत्ति में वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने और मुकदमे की संपत्ति में ताला तोड़कर जबरन कब्जा करने से रोकने का अनुरोध किया गया था। इस तरह के आवेदन पर, विद्वत विचारण न्यायाधीश ने यथास्थिति का अंतरिम आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ

प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की, जिसकी सुनवाई एक खंड पीठ ने की और उक्त खंड पीठ ने आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि निषेधाज्ञा के लिए मुख्य आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना बाकी था। वादी ने पुलिस की मदद से यथास्थिति के उक्त अंतरिम आदेश को लागू करने के लिए सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर किया और विद्वत विचारण न्यायालय के न्यायाधीश ने आवेदन को स्वीकार कर लिया। प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण दायर किया लेकिन उच्च न्यायालय ने इस आधार पर उक्त आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जब तक यथास्तिथि का अंतरिम आदेश मौजूद था, आदेश के कार्यान्वयन में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद, आदेश 39 नियम 4 सी. पी. सी. के तहत प्रतिवादी द्वारा पहले के अंतरिम आदेश को हटाने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने नोट किया कि उसने सामान्य रूप से आदेश 39 नियम 4 सी. पी. सी. के तहत आवेदन पर तथा गुण दोष पर निषेधाज्ञा के लिए मूल आवेदन में दायर लिखित आपत्ति पर विचार करने के लिए मामले को विद्वत परीक्षण न्यायाधीश को भेज दिया होगा । लेकिन यह इंगित किया गया कि वाद में, वादी ने प्रतिवादी के तीन बेटों को शामिल नहीं किया था जो प्रतिवादी के साथ संपत्ति के स्वीकृत रू से सह-मालिक बन गए थे और इस तरह संपत्ति के सभी सह-मालिकों की अनुपस्थिति में मुकदमे में निषेधाज्ञा का कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं

किया जा सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उन परिस्थितियों में यह एक उपयुक्त मामला था जहां वादी द्वारा दायर निषेधाज्ञा के लिए आवेदन को मुकदमे के लिए आवश्यक पक्षों की अनुपस्थिति में खारिज किया जाना था और केवल उसी आधार पर आवेदन खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह मामले के गुण-दोष में नहीं गया था और केवल तकनीकी आधार पर, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया था। अपील की अस्वीकृति को देखते हुए आवेदन सं .CAN 1209/ 2005 निष्फल हो गया था।

4. अपील की सुनवाई के दौरान, मूल वादी, रवींद्र कुमार शॉ के कानूनी उत्तराधिकारी अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला नहीं किया था और केवल इस तकनीकी आधार पर विवादित आदेश पारित किया था कि प्रतिवादी के तीन बेटे जो सह-मालिक हैं, उन्हें शामिल नहीं किया गया था। वास्तव में बाद में प्रतिवादी के तीन बेटों को शामिल के लिए धारा 151 सी. पी. सी. के साथ पठित आदेश 1 नियम 10 (2) के संदर्भ में वादी द्वारा 8.11.2005 को एक आवेदन दायर किया गया था। प्रार्थना को विचारण न्यायाधीश द्वारा दिनांक 19.4.2005 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

5. चूंकि प्रतिवादी के तीन बेटों के पक्षकार बयाए जाने को देखते हुए आवेदन की स्थिरता के बारे में मूल आपत्ति अब बनी नहीं है, इसलिए मामलों की नए सिरे से सुनवाई की जानी चाहिए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने कहा कि वह मामले के गुण-दोष में नहीं गया था और प्रतिवादी के तीन बेटों को शामिल न करने के तकनीकी आधार पर , अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया था। बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए हम मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए निचली अदालत को भेजते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिवादी के तीन बेटों के पक्षकार बनाये जाने के प्रभाव पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा।

6.अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

आर. पी.

अपीलों का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u> - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।